भारत–पाक संबंधः अतीत और सम्भावनाएँ

डॉ. महेन्द्र चौधरी
सहायक आचार्य (इतिहास)
सेठ आर.एल.सहरिया राजकीय
महाविद्यालय, कालाडेरा (जयपुर)

किसी भी देश की विदेश नीति वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में उस देश के आन्तरिक महत्त्व और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी देश की विदेश नीति की संरचना और उसकी गतिशीलता के पीछे उस देश का इतिहास, उसकी भौगोलिक परिस्थिति, दार्शनिक व वैचारिक पहलुओं और आर्थिक व सामाजिक शक्तियों का आधार होता है।

जब द्वितीय महायुद्ध के अन्त होने के बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की एक के बाद दूसरी कड़ियां–बेड़ियां टूटने लगी, तब यह स्मरणीय है कि भारत की दासता की कड़ियां–बेड़ियां पहले टूटी और उनके टूटते ही जैसे साम्राज्यवाद के दुर्ग तेजी से धराशायी होते गये, जैसे एक संसारव्यापी भूचाल आ गया हो। भारत, बर्मा, हिन्दचीन, इण्डोनेशिया, पश्चिम एशिया के अनेक देश तेजी से आजाद होते चले गए। द्वितीय महायुद्ध के बाद साम्राज्यवादियों के हाथों जो देशों के बंटवारे का सिलसिला चला जिसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के दो–तीन टुकड़े हो गए, भारत भी उनमें एक था।[1]

25 जुलाई 1947 को लार्ड माउण्टबेटन ने अपने एक बयान में कहा था कि ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के भारत सक समाप्त होने के बाद देशी रियासतें स्वतन्त्र होगी, उनकी यह इच्छा पर निर्भर होगा कि वे भारत में मिलें अथवा पाकिस्तान में मिलें अथवा स्वतन्त्र रहें परन्तु ऐसा उन्हें अपनी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए।[2]

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत का बँटवारा करके पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तान की स्थापना कर दी। भारत व पाकिस्तान के मध्य विवादों का सिलसिला रियासतों के विलय को लेकर हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू तथा कश्मीर रियासतों को लेकर हुई, किन्तु जूनागढ़ और हैदराबाद चारों ओर से भारतीय रियासतों से घिरी हुई थी एवं कुछ दिक्कतों के बाद इनका विलय भारत में हो गया। जम्मू तथा कश्मीर रियासत के महाराजा हरिसिंह ने प्रारम्भ में तो अपनी रियासत को भारत व पाकिस्तान किसी भी देश में नहीं मिलाया किन्तु बाद में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त के विभिन्न कबीलों के आक्रमण से उत्पन्न संकटकालीन स्थितियों में भारत में विलय के हस्ताक्षर किये।[3] कश्मीर का भारत में विलय दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बन गया। लाहौर में 8 दिसम्बर 1947 की भारत और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों की बैठक की असफलता के बाद लार्ड माउण्टबेटन को यह विश्वास हो गया कि दोनों देशों में पत्र व्यवहार से कश्मीर समस्या का हल निकलना असम्भव है। अतः इस मसले को संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया।[4] इसके अलावा भारत एवं कश्मीर के मध्य नहर जल विवाद उत्पन्न हो गया इसके समाधान हेतु 19 सितम्बर 1960 को विश्व बैंक की दखल से दोनों देशो के मध्य नहरी पानी समझौता हो गया।

कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए एक के बाद दूसरी योजनाएं बनाई। मेकनाटन योजना, डिक्सन मिशन, ग्राहम मिशन, जारिंग मिशन आदि आयोगो के माध्यम से कश्मीर समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया किन्तु सब प्रयास विफल हो गये। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने पाकिस्तान के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि दोनों देशों में युद्ध–विराम रेखा को ही स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा

मान ली जाये।[5] यह प्रस्ताव भी पाकिस्तान द्वारा ठुकरा दिया गया। भारत व पाकिस्तान के मध्य एक और विवाद का कारण कच्छ का रन बना। भारत सरकार को 25 जनवरी, 1965 को यह पता चला कि पाकिस्तान ने कच्छ की 18 मील लम्बी और डेढ़ मील चौड़ी पट्टी पर अधिकार कर लिया है और 30 जून 1965 को दोनों देशों के मध्य कच्छ के समझौते पर हस्ताक्षर हो गये। इसके पश्चात पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण की योजना बनायी। चीन की सहायता से पाकिस्तान की सरकार ने अपने द्वारा अधिकृत कश्मीर के लोगों को तथा अपनी सेना के नियमित सैनिकों को गुरिल्ला–युद्ध का प्रशिक्षण दिया। 1 सितम्बर 1965 को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तानी सेना ने छम्ब–जोरियाँ क्षेत्र (कश्मीर) पर अनेक टैंकों से आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की निर्याणक विजय हुई।[6]

4 जनवरी 1966 को रूस के प्रसिद्ध नगर ताशकन्द में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां के मध्य 'ताशकन्द समझौता' हुआ। 1966 में मुजीब ने आरोप लगाया कि पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा की जा रही है। 1971 में पाकिस्तान ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। 03 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान की वायु सेना ने अचानक शाम 6 बजे कई स्थानों पर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह युद्ध 15 दिन तक चलां 16 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट ए.ए.के.नियाजी ने आत्म समर्पण कर दिया। इसके साथ ही बंगलादेश पूर्णरूप से पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त हो गया। इसके पश्चात् 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ।

अप्रेल 1978 में पाकिस्तान के वैदेशिक मामलों के सलाहकार श्री आगाशाही की भारत यात्रा के समय सलाल पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्ष हुए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार में भी वृद्धि की गई।

भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव का मुख्य कारण कश्मीर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जिनेवा के मानवाधिकार आयोग में इस बात पर झड़प हो गई थी कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि आगाहिलाली ने कश्मीर का उल्लेख पारम्परिक तौर पर किया जिससे भारत सहमत नहीं है।[7]

1980 के दशक में भारत और पाकिस्तान संबंध जहां सामान्यीकरण की ओर अग्रसर दिखाई देते है वहीं दूसरी ओर तनाव उत्पन्न हो जाता है विशेषतौर पर कश्मीर के मामले को लेकर। इस तरह भारत–पाक संबंधों में निरन्तर प्रगति हुई है, तो दूसरी आरे कई बार गतिरोध उत्पन्न हो गए जिनमें संबंधों का तनावपूर्ण रहना स्वाभाविक था। इंदिरा युग में भारत – पाकिस्तान संबंधों को सामान्य तो नहीं कह सकते लेकिन तनाव कम करने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दृष्टिकोण बहुत साफ था कि समस्याओं के शांतिपूर्ण हल ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का आधार है और स्थानीय आंकाक्षाओं के अनुरूप ही उन्हें सुलझाना आवश्यक है।

भारत और पाकिस्तान के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य की अपार संभावनाएं है तथा दोनों देश आपसी सहयोग कर भारतीय उपमहाद्वीप में शांति बनाये रखते हुए विकास कर सकते है।

सन्दर्भ –

[1] हरगोविन्द पंत, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधः अधुनातन परिवेश में, जयपुर, 1982, पृ. 311.

[2] आर. सी. अग्रवाल, भारत की विदेश नीति, ग्वालियर, 1976ए पृ. 111.

[3] वी. पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ दि इंटीग्रेशन ऑफ स्टेटस, दिल्ली, 1956, पृ. 396–397.

[4] वही, पृ. 408–409.

[5] कुलदीप नैयर, डिस्टेंट नेबर्स, 1972, पृ. 85 एवं डॉ. कृष्णदेव कुसेदिया, विश्व राजनीति में भारत, पृ. 145–146.

[6] आर. सी. अग्रवाल, भारत की विदेश नीति, ग्वालियर, 1976, पृ. 165.

[7] हरगोविन्द पंत, अन्तर्राष्ट्रीय संबंधः अधुनातन परिवेश में, जयपुर, 1982, पृ. 342.